

000033



::आयुक्त (अपील्स) का कार्यालय, वस्तु एवं सेवा कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क::
O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), GST & CENTRAL EXCISE,



द्वितीय तल, जी एस टी भवन / 2nd Floor, GST Bhavan,
रेस कोर्स रिंग रोड, / Race Course Ring Road,
राजकोट / Rajkot - 360 001

Tele Fax No. 0281 - 2477952/2441142 Email: cexappealsrajkot@gmail.com

रजिस्टर्ड डाक ए. डी. द्वारा :-

क	अपील / फाइल संख्या Appeal / File No.	मूल आदेश सं / O.I.O. No.	दिनांक / Date
	V2/74/GDM/2016	ST/386/2016-17	07.10.2016

6517-706521

ख अपील आदेश संख्या (Order-In-Appeal No.):

KCH-EXCUS-000-APP-136-2017-18

आदेश का दिनांक / Date of Order:	18.12.2017	जारी करने की तारीख / Date of issue:	20.12.2017
------------------------------------	-------------------	--	-------------------

कुमार संतोष, आयुक्त (अपील्स), राजकोट द्वारा पारित /
Passed by Shri Kumar Santosh, Commissioner (Appeals), Rajkot

ग अथवा आयुक्त/सहायक आयुक्त/उपायुक्त/सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सेवाकर, राजकोट / जामनगर / गंधीधाम, द्वारा उपरलिखित जारी मूल आदेश से सूचित /
Arising out of above mentioned OIO issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissioner, Central Excise / Service Tax, Rajkot / Jamnagar / Gandhidham

घ **अपीलकर्ता & प्रतिवादी का नाम एवं पता /Name & Address of the Appellant & Respondent :-**
M/s. Rusan Pharma Ltd.,Grinding Unit, Plot No. 59 - 65, Sector II, Kandla Special Economic Zone, Gandhidham - 370 230

इस आदेश(अपील) से व्यक्त कोई व्यक्ति निम्नलिखित तरीके में उपयुक्त प्राधिकारी / प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है।/
Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following way,

(A) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपील विन्यायपत्रिका के प्रति अपील, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35B के अंतर्गत एवं वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 के अंतर्गत निम्नलिखित जगह की जा सकती है।/
Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section 35B of CEA, 1944 / Under Section 86 of the Finance Act, 1994 an appeal lies to:-

(i) विशेष न्यायालय में सम्बन्धित सभी मामले सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपील विन्यायपत्रिका की विशेष पीठ, वेस्ट ब्लॉक नं 2, पुरम, नई दिल्ली, को की जायी चाहिए।/
The special bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No. 2, R.K. Puram, New Delhi in all matters relating to classification and valuation.

(ii) उपरोक्त पैराग्राफ 1(a) में बताए गए अपीलों के अलावा सभी अपीलों सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपील विन्यायपत्रिका (विस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, द्वितीय तल, बहामली भवन असावा अहमदाबाद, 360016 को की जायी चाहिए।/
To the West regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at 2nd Floor, Bhaumali Bhawan, Asarwa Ahmedabad-380016 in case of appeals other than as mentioned in para- 1(a) above

(iii) अपील विन्यायपत्रिका के समक्ष अपील दस्तुन करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) नियमवली, 2001, के नियम 6 के अंतर्गत निर्धारित फॉर्म एवं फीस EA-3 को धार पत्रियों में दर्ज किया जाना चाहिए। इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की राशि अथवा सेवा कर जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का अग्रतान, संबंधित अपील विन्यायपत्रिका की शाखा के सहायक रजिस्ट्रार के नाम में किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेकॉर्डिंग बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का अग्रतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपील विन्यायपत्रिका की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्टै ऑर्डर) के लिए अग्रतान-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।/
The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 / as prescribed under Rule 6 of Central Excise (Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against one which at least should be accompanied by a fee of Rs. 1,000/- Rs.5000/-, Rs.10,000/- where amount of duty demand/interest/penalty/refund is upto 5 Lac. 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asst. Registrar of branch of any nominated public sector bank of the place where the bench of any nominated public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated. Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs. 500/-

(B) अपील विन्यायपत्रिका के समक्ष अपील, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86(1) के अंतर्गत सेवाकर नियमवली, 1994, के नियम 9(1) के तहत निर्धारित फॉर्म S.T.-5 में धार पत्रियों में की जा सकती है एवं उसके साथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो, उसकी प्रति साथ में संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां सेवाकर की राशि अथवा सेवा कर जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का अग्रतान, संबंधित अपील विन्यायपत्रिका की शाखा के सहायक रजिस्ट्रार के नाम में किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेकॉर्डिंग बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का अग्रतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपील विन्यायपत्रिका की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्टै ऑर्डर) के लिए अग्रतान-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।/
The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act, 1994, to the Appellate Tribunal Shall be filed in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1994, and shall be accompanied by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fee of Rs. 1000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied of Rs. 5 Lakhs or less, Rs.5000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than five lakhs but not exceeding Rs. Fifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the Assistant Registrar of the bench of nominated Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is situated. / Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs.500/-

The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act, 1994, to the Appellate Tribunal Shall be filed in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1994, and shall be accompanied by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fee of Rs. 1000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied of Rs. 5 Lakhs or less, Rs.5000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than five lakhs but not exceeding Rs. Fifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the Assistant Registrar of the bench of nominated Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is situated. / Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs.500/-



(i) विल अपीलियम, 1994 की धारा 86 की उप-धाराओं (2) एवं (2A) के अंतर्गत दर्जे की नवीं अपील, सेवाकर नियमवली, 1994, के नियम 9(2) एवं 9(2A) के तहत निर्धारित प्रार S.T.-7 में की जा सकती एवं उसके साथ आयकर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा अनुसूक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा पालन आदेश की प्रतियाँ संलग्न करे (जन्मे से एक प्रति प्रामाणित होनी चाहिए) और अनुसूक्त द्वारा सहायक आयकर अथवा उत्पाद शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवाकर, को अपीलिय न्यायाधिकरण को आवेदन दर्जे करने का निर्देश देने वाले आदेश की प्रति भी साथ में संलग्न करनी होगी। /
The appeal under sub section (2) and (2A) of the section 86 the Finance Act 1994, shall be filed in Form ST.7 as prescribed under Rule 9 (2) & 9(2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise (Appeals) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissioner authorizing the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise/ Service Tax to file the appeal before the Appellate Tribunal.

(ii) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलिय न्यायाधिकरण (सेक्टर) के प्रति अपील के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपीलियम 1944 की धारा 35एक के अंतर्गत, जो की विलीय अपीलियम, 1994 की धारा 83 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, इन आदेश के प्रति अपीलिय न्यायाधिकरण में अपील करने समय उत्पाद शुल्कपूर्वका कर भाग के 10 प्रतिशत (10%), जब मात्र एवं दुर्मीमा विवादित है, या दुर्मीमा, जब केवल दुर्मीमा विवादित है, का भुगतान किया जाए, बशर्त कि इन धारा के अंतर्गत जमा कि जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रुपए से अधिक न हो।
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत 'मान किए गए शुल्क' में विन्म शामिल है।

- (i) धारा 11 डी के अंतर्गत रकम
- (ii) सेक्टर जमा की गई राशि
- (iii) सेक्टर जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम

- बशर्त कि इन धारा के अंतर्गत विलीय (सं. 2) अपीलियम 2014 के अन्तर्ग से पूरे किसी अपीलिय न्यायाधिकारी के समक्ष विचारणीय स्थान नहीं एवं अपील को लागू नहीं होगी।

For an appeal to be filed before the CESTAT, under Section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under Section 83 of the Finance Act, 1994, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute, provided the amount of pre-deposit payable would be subject to a ceiling of Rs. 10 Crores.

Under Central Excise and Service Tax, "Duty Demanded" shall include :

- (i) amount determined under Section 11 D;
- (ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
- (iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules

- provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.

(C) भारत सरकार को पुनरीक्षण आवेदन :
Revision application to Government of India:

इस आदेश की पुनरीक्षण प्रक्रिया निम्नलिखित मामलों में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपीलियम, 1994 की धारा 35EE के प्रथम परलोक के अंतर्गत अथवा सचिव, भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन इकाई, विल संशोधन, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद भवन, नई दिल्ली-110001, को किया जाता चाहिए। /
A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case- governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35E ibid:

(i) यदि जाल के किसी अवस्था के मामले में, जहां नुकसान किसी जाल को किसी कारखाने से भंडार गृह के पराम्पर के दौरान या किसी अन्य कारखाने या फिर किसी एक भंडार गृह से दूसरे भंडार गृह पराम्पर के दौरान, या किसी भंडार गृह में या भंडारण में जाल के पराम्पर के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में जाल के नुकसान के समझे में। /
In case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse.

(ii) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात कर गई जाल के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे जाल पर डी गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के छुट (रिबेट) के मामले में, जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात की गयी है। /
In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.

(iii) यदि उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर, नेपाल या भूटान को जाल निर्यात किया गया है। /
In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.

(iv) प्रतिनिधित उत्पाद के उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो इप्टी केडीट इस अपीलियम एवं इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो आवकर (अपील) के द्वारा विल अपीलियम (सं. 2), 1998 की धारा 109 के द्वारा नियत की गई तरीक अथवा स्लावविधि पर या बट में परित किए गए हैं। /
Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998.

(v) उपरोक्त आवेदन की दो प्रतियां प्रथम संख्या EA-8 में, जो की केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमवली, 2001, के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, इन आदेश के संकेत के 3 माह के अंतर्गत की जानी चाहिए। उपरोक्त आवेदन के साथ मूल आदेश व अपील आदेश की दो प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए। साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपीलियम, 1944 की धारा 35-EE के तहत निर्धारित शुल्क की अदायगी के संबंध के लिए पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। /
The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-in-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

(vi) पुनरीक्षण आवेदन के साथ निम्नलिखित निर्धारित शुल्क की अदायगी की जानी चाहिए। /
जहाँ संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम हो तो रुपये 200/- का भुगतान किया जाए और वहाँ संलग्न रकम एक लाख रुपये से ज्यादा हो तो रुपये 1000 -/ का भुगतान किया जाए। /
The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- where the amount involved in Rupees One Lac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

(D) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए शुल्क का भुगतान, उपरोक्त इस से किया जाना चाहिए। इस तथ्य के होते हुए भी की निम्न पट्टी आवेदों से बचने के लिए सहायक अपीलिय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है। /
In case, if the order covers various numbers of order-in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellate Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filed to avoid scripps work if excising Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each.

(E) न्यायाधिकरण न्यायालय शुल्क अपीलियम, 1975, के अनुसूची-1 के अनुसार मूल आदेश एवं स्थान आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का न्यायालय शुल्क टिकिट लगा होना चाहिए। /
One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs. 6.50 as prescribed under Schedule-I in terms of the Court Fee Act,1975, as amended.

(F) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलिय न्यायाधिकरण (कार्य विधि) नियमवली, 1982 में वर्णित एवं अन्य संबंधित मामलों को सम्बन्धित करने वाले विधियों की और भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। /
Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

(G) उच्च अपीलिय न्यायाधिकारी को अपील दर्जित करने से संबंधित व्यापक, विस्तृत और नवीनतम प्रावधानों के लिए, अपीलिय विभागीय वेबसाइट www.cbec.gov.in को देख सकते हैं। /
For the elaborate, detailed and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental website www.cbec.gov.in

:: ORDER-IN-APPEAL ::

000051

M/s. Rusan Pharma Ltd., Plot No. 59 to 65, Sector-II Kandla Special Economic Zone, Gandhidham-370 230, Kutch, Gujarat (hereinafter referred to as 'the appellant') has filed the present appeal against the Order-In-Original No. ST/386/2016-17 dated 07.10.2016 (hereinafter referred to as 'the impugned order'), passed by the Assistant Commissioner, Service Tax Division - Gandhidham-Kutch (hereinafter referred to as "the lower adjudicating authority").

2. Briefly stated facts of the case are that the appellant is holding Service Tax registration No. AABCR3179HSE003 under the taxable service "Transport of Goods by Road/Goods Transport Agency Service" etc. The appellant is a manufacturer situated in KASEZ, Gandhidham Kutch District holding valid Letter of Approval (LOA) issued vide No. KFTZ/1790/2000 dated 27.07.2000, Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce. They are availing the benefit of exemption of service tax paid by them for specified services received and used exclusively for authorized operations by virtue of Notification No. 12/2013-ST dated 01.07.2013. The appellant has filed an application for refund of service tax for Rs. 9,52,172/- on 19.08.2016 covering period from April to June, 2016, under Notification No. 12/2013-ST.

3. However, the lower adjudicating authority vide impugned order sanctioned refund of Rs. 3,38,658/- and rejected refund of Rs. 6,13,514/- on the grounds that the LOA letter was missing and invoice issued by Core Technologies doesn't contain the Service Tax number, which was asked for from the appellant vide letter dated 15.09.2016 but the appellant has not replied. The lower adjudicating authority thus held that Rs. 6,13,514/- is deductible from the claim as they had claimed refund of Service Tax on vehicle insurance, invalid invoice, service not covered under approval list and name and address didn't match.

4. Being aggrieved by the impugned order, appellant preferred the present appeal, inter-alia, on the following grounds:

- (i) Invoices listed at Sr. No. 2 & 3 rejected claim showing reason that Vehicle Insurance is not covered under the list of specified services approved by the approval committee of SEZ, on which refund has been claimed. The said service is available at Sr. No. 27 as "General Insurance Business Services" in a list of specified services approved by the approval committee of SEZ.

- (ii) Invoice listed at Sr. No. 7 is invalid and the lower adjudicating authority has not shown proper reasons & grounds for rejection of the refund claim.
- (iii) Invoice listed at Sr. No. 8, 12 & 19 services not covered under the approval list. The invoices listed at Sr. No. 8 & 19 pertain to Outdoor Catering Services and Hotel Services, which is available at list specified services approved by the approval Committee of SEZ at Sr. No. 38 as "outdoor catering services" and Sr. No. 66 as "Accommodation Services". Thus both the services are available in the list of specified services.
- (iv) Sr. No. 12 pertain to Mandap Services which is available for the promotion and development of the business of the company and thus the same is covered under the category of "Business Support Services".
- (v) Invoice listed at Sr. No. 15 wherein the lower adjudicating authority has observed that name and address didn't matched. In this regard they submitted that the invoice issued in the name of the company but address is mentioned for Head Office instead of KASEZ Gandhidham and there is no malafide intention but the same is done by mistake and thus refund cannot be denied.

5. A personal hearing in the matter was attended by Shri Sunil Adtani, Account Manager who reiterated grounds of appeal and submitted written submissions. He added no further statement during personal hearing. The written submission submitted during the course of personal hearing is akin to the grounds of appeal stated above.

FINDINGS:

6. I have carefully gone through the facts of the case, the impugned order, the appeal memorandum and written and oral submissions made by the appellant. The issue to be decided in the present case is as to whether the appellant was eligible for Refund of Service Tax paid by them on specified services approved by the approval committee of SEZ or not.

7. I find that the lower adjudicating authority has rejected the refund claim for services tax by stating reason as "Vehicle Insurance", "Invalid Invoice", "Service not covered under approved list" and "name & address didn't match"

7.1 On going through the impugned order, I find that neither Show Cause Notice


has been issued nor reasonable opportunity of being heard given to the appellant for rejection of refund, which is a clear case of violation of principles of natural justice.

7.2 I find that this is a fit case to set aside the impugned order and allow the appeal by way of remand to lower adjudicating authority on this ground alone with direction to lower adjudicating authority to decide the matter within 3 months from the date of receipt of this order after giving fair and reasonable opportunity to the appellant. The appellant is also directed to submit the required documents to the lower adjudicating authority for decision in the matter within one month from receipt of this order.

7.3 The Commissioner (Appeals) has power to remand as has been decided by the Hon'ble CESTAT in the case of CCE, Meerut Vs. Singh Alloys (P) Ltd. reported as 2012(284) ELT 97 (Tri-Del). I also rely upon decision of the Hon'ble Tribunal in the case of CCE, Meerut-II Vs. Honda Seil Power Products Ltd. reported in 2013 (287) ELT 353 (Tri-Del) wherein the similar views have been expressed in respect of inherent power of Commissioner (Appeals) to remand a case under the provisions of Section 35A of the Act. The Hon'ble Gujarat High Court in Tax Appeal No. 276 of 2014 in respect of Associated Hotels Ltd. has also held that even after the amendment in Section 35A (3) of the Central Excise Act, 1944 after 11.05.2011, the Commissioner (Appeals) would retain the power to remand.

8. Before parting with the case, I would like to record that the contention of the appellant that the specified services on which refund has been rejected are duly approved by the Approval Committee of SEZ as listed therein. Further, rejecting of refund has been held on invalid invoice, however, the lower adjudicating authority has not given proper reason as to why the said invoice has been treated as invalid invoice. Therefore, the impugned order rejecting refund is set aside and appeal is allowed by way of remand to be decided as directed in Para 7.2 above.

९. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है ।
9. The appeal filed by the appellant is disposed of in above terms.


 (कुमार संतोष)
 आयुक्त (अपील्स)